भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2699 का उत्तर

रेलवे के सामने आने वाली अभिज्ञेय अवसंरचनात्मक बाधाएं

2699. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल कतिपय अभिज्ञेय अवसंरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये बाधाएं न केवल दक्षता को बाधित करती हैं बल्कि परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हुए रेल माल ढुलाई प्रचालनों की क्षमता को सीमित करती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या आर्थिक विकास और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए रेल मालभाड़े की हिस्सेदारी में वृद्धि करना आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा रेलवे की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और संवहनीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): 'भविष्य के लिए तैयार' परिवहन प्रणाली बनाने के लिए, भारतीय रेल ने राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य माल ढुलाई में रेलवे मॉडल हिस्सेदारी को 35-45% तक बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतिगत पहलों दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना है।

योजना का उद्देश्य "मांग से पूर्व क्षमता सृजन" है, जो बदले में परिवहन क्षेत्र में भविष्य के विकास को पूरा करेगा। रेल अवसंरचना संवर्धन योजना अन्य बातों के साथ-साथ नेटवर्क क्षमता संवर्धन, अवरोधों को दूर करने, मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाने, कार्गो ट्रांजिट समय और लागत में कमी करने पर ध्यान दिया जाता है।

वर्तमान में, एकीकृत योजना, लाजिस्टिक दक्षता बढ़ाने और औद्योगिक क्लस्टरों बंदरगाहों, खानों, बिजली संयंत्रों, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों, कृषि क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सहित यात्रियों और माल की निर्बाध आवाजाही के लिए एकीकृत योजना लॉजिस्टिक कुशलता को बढ़ाने और बाधाओं को हटाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेल पर कुल 49,520 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 624 सर्वेक्षण (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) शुरू किए गए हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 परियोजनाएं (187 नई लाइनें, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई की परियोजना चालू की जा चुकी है और मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक कुल व्यय (करोड़ में)
नई लाइनें	187	20,199	2,855	1,60,022
आमान परिवर्तन	40	4,719	2,972	18,706
दोहरीकरणमल्टीट्रैकिंग/	261	19,570	6,218	1,13,742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्रवार/वर्षवार ब्यौरा पब्लिक डोमेन में भारतीय रेल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

भारतीय रेल पर कमीशन किए गए/बिछाए गए रेलपथों का ब्यौरा नीचे दिया गया है

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	औसतन कमीशन किए गए नये रेलपथ
2009-14	7,599 कि.मी	4.2 कि.मी./दिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी./दिन (दो गुना से ज्यादा)

रेल परियोजनाओं के शीघ्र अनुमोदन और कार्यान्वयन सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं को प्राथमिकता (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) क्षेत्र स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की सघन निगरानी, और (vi) भूमि अधिग्रहण, वन संबंधी और वन्यजीव मंजूरी में तेजी लाने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारतीय रेल अपने बडी लाइन नेटवर्क का 97% विद्युतीकरण हासिल किया है जो प्रमुख देशों के बीच वैश्विक स्तर के सतत परिवहन के लिए एक उपलब्धि है। पर्यावरणीय स्थिरता और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के अलावा, रेलवे द्वारा उठाए गए कदम भी ईंधन दक्षता बढ़ाने और विदेशी मुद्रा बचाने में योगदान देंगे।

कार्गो टर्मिनलों पर दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, "गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)" नीति शुरू की गई है, जिसमें गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं। अब तक 91 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, अब तक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के 2,843 किलोमीटर में से कुल 2,741 किलोमीटर कमीशन किया जा चुका है, जो उच्च माल ढुलाई गति, कार्गो पारगमन को कम करेगा और कम कार्बन उत्सर्जन प्रदान करेगा।

*****